

पत्रांक: 986/पी0एम0आई0एस0/2024-25

दिनांक: 03 दिसम्बर, 2024

प्रेषक:

संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)  
क्षेत्रीय कार्यालय, दून विश्वविद्यालय परिसर  
देहरादून।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य  
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय  
उत्तराखण्ड।

**विषय: Prime Minister Internship Scheme-Pilot Project (F.Y. 2024-25) योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, (प्रशिक्षण), प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्रांक: 12061-61/डी0टी0ई0यू0/शि0प्रशि0/पी0एम0-आई0एस0/2024 दिनांक 26 नवम्बर, 2024 (प्रति संलग्न) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक: 253039/XXVII(1)2024 दिनांक 11 नवम्बर, 2024 (प्रति संलग्न) एवं अपर निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी के पत्रांक: 9879-85/डी0टी0यू0/शि0प्रशि0/पी0एम0-आई0एस0/2024 दिनांक 13 नवम्बर, 2024 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में Prime Minister Internship Scheme-Pilot Project (F.Y. 2024-25) योजना (प्रति संलग्न) के क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे संलग्नक पत्रों का संज्ञान लेते हुए अपने संस्थान में उक्त योजना से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करते हुए आवेदकों को लाभान्वित करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उक्तवत्।

भवदीय

(प्रो0 ए0एस0 उनियाल)

संयुक्त निदेशक  
क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा  
देहरादून

पृ0सं0: 986(i-ii)/पी0एम0आई0एस0/2024-25 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
2. निदेशक, (प्रशिक्षण), प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

प्रेषक,

निदेशक (प्रशिक्षण),  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

उ०शि०नि० उत्तराखण्ड  
प्राप्ति तिथि 29/11/24  
डिप्टी प्रिन्सिपल  
प्राप्ति रजि० क्रमांक 2882

सेवा में,

- |   |   |
|---|---|
| 1. महानिदेशक,<br>विद्यालयी शिक्षा विभाग,<br>उत्तराखण्ड। | 2. ✓ निदेशक,<br>उच्च शिक्षा विभाग,<br>उत्तराखण्ड। |
| 3. निदेशक,<br>तकनीकी शिक्षा विभाग,<br>उत्तराखण्ड।       | 4. निदेशक,<br>उद्योग विभाग,<br>उत्तराखण्ड।        |

पत्रांक:- 12061-66 / डीटीईयू/शि०प्रशि०/पीएम-आईएस/2024

दिनांक: 26 नवम्बर, 2024

विषय- Prime Minister Internship Scheme- Pilot Project (Financial Year 2024-25) योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के अधीन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक संख्या: CSR/13/35/2024 दिनांक: 03 अक्टूबर, 2024 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक संख्या: 253039/XXVII(1)/2024 दिनांक: 11 नवम्बर, 2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में Prime Minister Internship Scheme- Pilot Project (Financial Year 2024-25) की घोषणा की गयी है। जिसका उद्देश्य देश में आगामी 05 वर्षों में 01 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कम्पनियों में Internship उपलब्ध कराया जाना है। योजना के माध्यम से युवाओं को विभिन्न व्यवसाय/रोजगार आदि में विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त होगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख Internship Opportunities लक्ष्यान्वित की गयी है। योजनान्तर्गत 21 से 24 वर्ष के युवा जो किसी पूर्ण कालिक रोजगार/शिक्षा में नहीं है एवं उनके परिवार से कोई सदस्य सरकारी सेवा में न हों तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 8.00 लाख से अधिक की आय न हो, पात्र होंगे। योजनान्तर्गत प्रत्येक Intern को ₹ 5000/- मासिक भत्ता (जिसमें से ₹ 4500/- Ministry of Corporate Affair को ₹ 500/- सम्बन्धित कम्पनी के CSR Fund से) एवं ₹ 6000/- One time grant के रूप में सरकार द्वारा आवेदक को DBT के माध्यम से दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण व्यय भी कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा।

2- उक्त पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन ऑनलाईन पोर्टल [www.pminternship.mca.gov.in](http://www.pminternship.mca.gov.in) के माध्यम से किया जाना है एवं पोर्टल पर योजना के पूर्ण दिशा निर्देश, आवेदकों के पंजीकरण व आवेदन करने की प्रक्रिया हेतु PPT एवं वीडियो भी उपलब्ध है।

3- प्रशिक्षण निदेशालय के पत्र दिनांक: 13 नवम्बर, 2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा जनपद स्तर पर प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के प्रभावी समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जनपद में 01 नोडल अधिकारी भी नामित किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने-अपने विभाग के समस्त महाविद्यालयों/विद्यालयों/पॉलीटेक्निक आदि में योजना से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करवाते हुये अधिकाधिक आवेदकों को लाभान्वित करवाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

( संजय कुमार )  
निदेशक (प्रशिक्षण)

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।

3. निदेशक (आई0टी0 एण्ड टी0टी0) प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, कौशल भवन, नई दिल्ली को सादर सूचनाार्थ ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, ग्रीन पार्क, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से यथा आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिशिक्षु) कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी/गढ़वाल मण्डल, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) को इस आशय से कि अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

( संजय कुमार )  
निदेशक (प्रशिक्षण)

( नामक बोर्ड )  
( प्रमुख )

-निदेशक-

(आचार्य) (प्रमुख) (संयुक्त) (संयुक्त) (संयुक्त) (संयुक्त) (संयुक्त) (संयुक्त) (संयुक्त) (संयुक्त) (संयुक्त)

प्रेषक,

अपर निदेशक (प्रशिक्षण),  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

सेवा में,

सहायक/उप शि शिक्षु परामर्शदाता/नोडल प्रधानाचार्य,  
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी/काशीपुर/टनकपुर/पिथौरागढ़/अल्मोड़ा/  
देहरादून/हरिद्वार/कर्णप्रयाग/बड़कोट/नई टिहरी/काण्डा/श्रीनगर/रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।

पत्रांक:- 9879-85 / डीटीईयू/शि0प्रशि0/पीएम-आईएस/2024

दिनांक: 13 नवम्बर, 2024

विषय-

**Prime Minister Internship Scheme- Pilot Project (Financial Year 2024-25) योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के अधीन कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक: 30 अक्टूबर, 2024 के क्रम में वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक संख्या: 253039/XXVII(1)/2024 दिनांक: 11 नवम्बर, 2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के अन्तर्गत आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र धारक प्रशिक्षार्थियों को शीर्ष कम्पनियों में इंटरनशिप का अवसर प्रदान किया जायेगा। प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना वर्ष 2024-25 से प्रथम बार प्रारम्भ की जा रही है। उक्त योजना को ऑनलाईन पोर्टल [www.pminternship.mca.gov.in](http://www.pminternship.mca.gov.in) के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने एवं योजना के प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जनपद में 01 नोडल अधिकारी नामित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

उक्त के क्रम में प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के प्रभावी समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जनपद में निम्नानुसार नोडल अधिकारी नामित किये जाते हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्रं सं०	जनपद का नाम	संस्थान का नाम	प्रधानाचार्य का नाम	मो० नं०	ई-मेल आई0डी0
1	2	3	4	5	6
1	अल्मोड़ा	रा0औ0प्रशि0 संस्थान, अल्मोड़ा।	श्री उदयराज सिंह	8194035386	iti.almora.ppp@gmail.com
2	बामेश्वर	रा0औ0प्रशि0 संस्थान, काण्डा।	श्री उदयराज सिंह	8194035386	iti.kanda.ppp@gmail.com
3	चमोली	रा0औ0प्रशि0 संस्थान, कर्णप्रयाग।	श्री दीपक कुमार चौधरी	7302663934	iti.karnprayag.ppp@gmail.com
4	चम्पावत	रा0औ0प्रशि0 संस्थान टनकपुर।	श्री कविन्द्र सिंह कन्याल	7302663932	iti.tanakpur.vtip@gmail.com
5	देहरादून	रा0औ0प्रशि0 संस्थान, देहरादून।	श्री मनमोहन कुड़ियाल	7302663914	iti.dehradunboys.uk@gmail.com
6	हरिद्वार	रा0औ0प्रशि0 संस्थान, हरिद्वार।	श्री अमित कल्याण	7302663935	iti.haridwar.vtip@gmail.com
7	नैनीताल	रा0औ0प्रशि0 संस्थान (युवक) हल्द्वानी	श्री पी0के0 धारीवाल	7302663929	iti.haldwaniboyes.uk@gmail.com
8	पौड़ी गढ़वाल	रा0औ0प्रशि0 संस्थान, श्रीनगर (पौड़ी)।	श्री संजीव कुमार	7302663913	iti.srinagar.vtip@gmail.com
9	पिथौरागढ़	रा0औ0प्रशि0 संस्थान, पिथौरागढ़।	श्री आर0एस0 मर्तोलिया	7302663927	iti.pithoragarh.vtip@gmail.com
10	रूद्रप्रयाग	रा0औ0प्रशि0 संस्थान, रूद्रप्रयाग।	श्री जगदीश चन्द्र	9411549412	iti.rudraprayag.ppp@gmail.com
11	टिहरी गढ़वाल	रा0औ0प्रशि0 संस्थान, नई टिहरी।	श्रीमती पल्लवी	7302663911	iti.newtehri.vtip@gmail.com
12	ऊधमसिंह नगर	रा0औ0प्रशि0 संस्थान (युवक) काशीपुर।	श्री जे0पी0 टम्टा	7500038178	iti.kashipur.uk@gmail.com
13	उत्तरकाशी	रा0औ0प्रशि0 संस्थान, बड़कोट।	श्री निरंजन खुगशाल	7302663910	iti.barkot.ppp@gmail.com

अतः उपरोक्त नोडल अधिकारियों को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक: 30 अक्टूबर, 2024 एवं शासन के पत्र दिनांक: 11 नवम्बर, 2024 की प्रति संलग्न करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के प्रभावी समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु अपने-अपने जनपद के जिलाधिकारी महोदय से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिससे अधिक से अधिक आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र धारक प्रशिक्षार्थियों को शीर्ष कम्पनियों में इंटरनशिप का लाभ प्राप्त हो सकें।  
**संलग्नक:-** उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

*(Handwritten Signature)*  
 ( ऋचा सिंह )

अपर निदेशक (प्रशिक्षण)

**प्रतिलिपि:-**

1. सचिव, कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
3. निदेशक (आई0टी0 एण्ड टी0टी0) प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, कौशल भवन, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, ग्रीन पार्क, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से यथा आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिशिक्षु) कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी/गढ़वाल मण्डल, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) को इस आशय से कि अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

*(Handwritten Signature)*  
 ( ऋचा सिंह )

अपर निदेशक (प्रशिक्षण)

क्र.सं.	नाम	पद	संस्था	सं.सं.
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...

8-79813

संख्या- 253039 / XXVII(1)/2024

महत्वपूर्ण प्राथमिकता

प्रेषक,

राधा स्तूडी  
मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/  
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त,  
कुमाऊं एवं गढ़वाल,  
उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी  
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 11 नवम्बर, 2024

विषय:- Prime Minister Internship Scheme- Pilot Project (Financial Year 2024-25)  
योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, भारत सरकार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के संलग्न पत्र दिनांक 30.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में Prime Minister Internship Scheme-Pilot Project (Financial Year 2024-25) की घोषणा की गयी है। जिसका उद्देश्य देश में आगामी 05 वर्षों में 01 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कम्पनियों में Internship उपलब्ध कराया जाना है। योजना के माध्यम से युवाओं को विभिन्न व्यवसाय/रोजगार आदि में विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त होगा। इस पायलेट प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख Internship opportunities लक्ष्यान्वित की गयी है। इस हेतु योजना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश दिनांक 03.10.2024 को भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये हैं। योजनान्तर्गत 21 से 24 वर्ष के युवा जो किसी पूर्ण कालिक रोजगार/शिक्षा में नहीं हैं एवं उनके परिवार से कोई सदस्य सरकारी सेवा में न हों तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में रु 8.00 लाख से अधिक की आय न हो, पात्र होंगे। योजनान्तर्गत प्रत्येक Intern को रु 5000/- मासिक भत्ता (जिसमें से रु 4500/- Ministry of Corporate Affair तथा रु 500/-सम्बन्धित कम्पनी के CSR Fund से) एवं रु 6000/- one time grant के रूप में सरकार द्वारा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण व्यय भी कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा।

2- योजना हेतु नोडल विभाग कौशल विकास विभाग है।

3- प्रश्नगत योजना के समन्वय हेतु डॉ० अहमद इकबाल, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

4- उक्त पायलेट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन ऑनलाईन पोर्टल [www.pminternship.mca.gov.in](http://www.pminternship.mca.gov.in) के माध्यम से किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नगत योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार समयबद्ध रूप दिनांक 15.11.2024 से पूर्व योजना के क्रियान्वयन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें। प्रकरण में समयबद्धता अपेक्षित है।

भवदीया

Signed by

Radha Raturi

Date: 11-11-2024 17:34:21

(राधा रतूडी)  
मुख्य सचिव

संख्या- 253039 /XXVII(1)/2024, तददिनांकित। 11/11/24

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. महा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कौशल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, उद्योग विभाग उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

Signed by

Ahmad Iqbal

Date: 11-11-2024 17:39:34 (डॉ० अहमद इकबाल)

अपरा सचिव

राधा रतूड़ी  
Radha Raturi



मुख्य सचिव  
Chief Secretary

उत्तराखण्ड शासन  
Government of Uttarakhand  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन  
Netaji Subhash Chandra Bose Bhawan  
राज्य सचिवालय, देहरादून  
Civil Secretariat, Dehradun  
Phone (Off.) 0135-2712100, 2712200  
(Fax) 0135-2712500  
E-mail : cs-uttarakhand@nic.in  
chiefsecyuk@gmail.com

अर्द्धशा0प0सं0: 5708 / नि.स.-मु.स. / 2024  
देहरादून : दिनांक 11 नवम्बर, 2024

आज दिनांक 11 नवम्बर, 2024 को आपसे दूरभाष पर हुयी वार्ता के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में PM Internship Scheme के लिए नोडल विभाग कौशल विकास विभाग है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सम्पर्क अधिकारी डा0 अहमद इकबाल, (आई.ए.एस.) अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन को नामित किया गया है।

डा0 अहमद इकबाल, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का दूरभाष नं0-09027776784 है।


भवदीया,

(राधा रतूड़ी)

सुश्री दीप्ती गौड़ मुखर्जी (आई0ए0एस0),  
सचिव,  
कॉरपोरेट मंत्रालय, भारत सरकार,  
नई दिल्ली।

प्रतिलिपि : मूल में नहीं।

1. सचिव, कौशल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. डा0 अहमद इकबाल, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

  
(राधा रतूड़ी)  
मुख्य सचिव



डिप्टी गौड़ मुकजी, आईएस

सचिव

Deepti Gaur Mukerjee, IAS  
Secretary



भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
नई दिल्ली

Government of India  
Ministry of Corporate Affairs  
New Delhi

D.O.No. PMIS-01/10/2024

30<sup>th</sup> October, 2024

Dear Ma'am,

I would like to draw your attention to the Prime Minister's Internship Scheme which was announced in the Budget 2024-25. The scheme aims to provide internship opportunities to one crore youth in the top 500 companies in five years. Through this Scheme, youth will gain exposure for 12 months to real life business environment, across varied professions and employment opportunities.

2. As an initiation of this ambitious Scheme, a pilot project targeted at providing 1.25 lakh internship opportunities for the financial year 2024-25 has been launched on 3<sup>rd</sup> October, 2024. The feedback received and the evaluation of outcomes during the implementation of the pilot project would be factored in while rolling out the full-fledged PM Internship Scheme. A copy of the guidelines issued on 3<sup>rd</sup> October, 2024 which were also addressed to you with a request to nominate a nodal officer for scheme implementation, is enclosed for your kind reference. This scheme is envisaged as a central sector scheme and would be in addition to other similar schemes, if any, being implemented in your State.

3. Youth eligible under the scheme are those who are between 21-24 years of age and are not in full time employment or education. Further, no member of their family should be a government employee or have an income of more than 8 lakh in the financial year 2023-24. Under the scheme, every intern will receive a monthly allowance of Rs. 5000 (out of which Rs. 4500 is to be paid by the Ministry of Corporate Affairs, and Rs. 500 by the company from its CSR funds) as monthly allowance, along with Rs. 6000 as a one-time grant for incidentals, to be paid by the Government. The training cost is to be borne by the Company, from its CSR funds. Further, insurance coverage shall be provided to each individual intern under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, for which premium amount shall be provided by the Central Government.

4. The pilot project is being implemented through an online portal [www.pminternship.mca.gov.in](http://www.pminternship.mca.gov.in). Companies have offered about 1.27 lakh internship opportunities covering 25 sectors, 36 States/UTs and 745 districts. The internship opportunities have been offered for youth who have passed High school (about 31,500), Higher Secondary (8,826), ITI certificate holders (about 30,448), Diploma holders (about 21,222) and Graduates (about 35,050). At present the process of registration and applications for internship is going on. Youth are able to explore the opportunities available, and apply for the offers as per their preferences and skills. At the national level, more than 2 lakh internship applications have been received so far. The number of internship opportunities offered by the top companies in your state are about 1,796. The details of the opportunities offered in your state are attached.

कमरा नं. 519, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

Room No. 519, 'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001

Phone : 91-11-23382324, 23384017, Fax : 91-11-23384257, E-mail : [secy.mca@nic.in](mailto:secy.mca@nic.in)

5. This scheme is an excellent opportunity for youth living in various districts of your state to gain exposure to business environment of top companies, enhance their technical and behavioural skills thereby improving their employability. I would request you to nominate a nodal Department for this scheme, as the opportunities offered are across all levels of education and requires a coordinated approach at the state level. We would collaborate with the above Department and seek their valuable support in implementing the scheme. We look forward to working with you so that the youth of your State are able to avail the unique opportunity offered by the Prime Minister's Internship Scheme - Pilot Project.

With regards,

Yours Sincerely,

(Deepti Gaur Mukerjee)

Encl: As above.

Ms. Radha S. Raturi,  
Chief Secretary,  
Government of Uttarakhand,  
Subhash Road,  
Dehradun 248- 001.

**District wise Internship Opportunity offered in UTTARAKHAND in PM Internship Scheme- Pilot Project**

Sl. No	District/ Qualification	Number of Internship Opportunities
1	Almora	12
	10th	2
	ITI	10
2	Bageshwar	3
	10th	1
	Diploma	2
3	Chamoli	37
	10th	2
	Diploma	4
	Graduation	8
4	ITI	23
	Champawat	62
	10th	1
	Graduation	45
5	ITI	16
	Dehradun	755
	10th	179
	12th	63
	Diploma	143
6	Graduation	253
	ITI	117
	Haridwar	319
	10th	149
	12th	46
7	Diploma	23
	Graduation	46
	ITI	55
	Nainital	107
	10th	29
8	12th	1
	Diploma	9
	Graduation	8
	ITI	60
	Pauri Garhwal	7
9	10th	2
	Graduation	1
	ITI	4
9	Pithoragarh	84
	10th	2

	Diploma	4
	Graduation	2
	ITI	76
10	Rudra Prayag	4
	10th	2
	ITI	2
11	Tehri Garhwal	80
	10th	2
	Diploma	22
	Graduation	21
	ITI	35
12	Udam Singh Nagar	280
	10th	7
	12th	30
	Diploma	44
	Graduation	33
	ITI	166
13	Uttar Kashi	46
	10th	1
	Diploma	6
	Graduation	2
	ITI	37
	<b>Total Internship opportunity in the State</b>	<b>1796</b>

F. NO- CSR/ 13/35/2024  
Government of India  
Ministry of Corporate Affairs  
(PMIS Cell)

\*\*\*\*\*

5<sup>th</sup> Floor, 'A' Wing, Shastri Bhawan,  
Dr. Rajendra Prasad Road,  
New Delhi-110 001

Dated: 03.10.2024

Office Memorandum

**Subject: Guidelines for "Prime Minister's Internship Scheme - Pilot Project (Financial Year 2024-25)"**

The Prime Minister's Internship Scheme in Top Companies has been announced in the Budget 2024-25 (Scheme). It aims to provide internship opportunities to one crore youth in top 500 companies in five years. Through this Scheme, youth will gain exposure for 12 months to real-life business environment, across varied professions and employment opportunities.

2. As an initiation of this ambitious Scheme which involves multiple stakeholders and innovative concepts of skilling, a Pilot Project of the Scheme targeted at providing 1.25 lakh internship opportunities is being launched for the Financial Year (FY) 2024-25. The top companies for this Pilot Project have been identified on the basis of the average of CSR expenditure of the last three years. Participation of the companies in this Scheme is voluntary. A list of these companies would be uploaded on the PM Internship Scheme Portal.

3. Internship, for the purpose of this Scheme is envisaged as an arrangement between the intern and the company in which the company provides an opportunity to the intern to get training, gain experience and skills within the real-life environment of the business or organization that helps in bridging the gap between academic learning and industry requirements, in turn, assisting enhancement of her/his employability.

4. **Scope:** The Scheme is separate from all the existing schemes related to skill development, apprenticeships, internship and student training programmes, etc. being implemented across all the States & UTs of India, and will run independently of all such Central/State schemes.

**5. Salient Features of the Pilot Project**

**5.1 Internship Duration:** Duration of the Internship shall be 12 months. At least half of the internship period must be spent in the actual working experience/ job environment, and not in the classroom.

## **5.2 Eligibility criteria for candidates**

**5.2.1 Age:** Youth aged between 21 and 24 (as on the last date for submission of application), belonging to Indian nationality, who are not employed full-time and not engaged in full-time education. Candidates enrolled in online/ distance learning programmes are eligible to apply.

**5.2.2 Educational Qualifications:** Candidates who have passed High School, Higher Secondary School, possess a certificate from an ITI, hold a diploma from a Polytechnic Institute, or are graduates with degrees such as BA, B.Sc, B.Com, BCA, BBA, B.Pharma, etc. are eligible.

**5.2.3 Ineligibility criteria:** The following persons are ineligible to participate:

- (i) Graduates from IITs, IIMs, National Law Universities, IISER, NIDs, and IIITs.
- (ii) Those having qualifications such as CA, CMA, CS, MBBS, BDS, MBA, any master's or higher degree.
- (iii) Those undergoing any skill, apprenticeship, internship or student training programme under Central Government or State Government schemes.
- (iv) Those who have completed apprenticeship, training under National Apprenticeship Training Scheme (NATS) or National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) at any point.
- (v) If the income of any of the family members of the candidate exceeds Rs 8 lakh for FY 2023-24.
- (vi) If any member of the family is a permanent/regular government employee.

**Note:** For the purposes of the Pilot Project:

- (i) "Family" means self, parents and spouse.
- (ii) "Government" means Central and State Governments, UT administration, Central and State PSUs, statutory organizations, local bodies etc.
- (iii) "Employee" means regular/ permanent employees but does not include contractual employees.

## **5.3 Criteria for the companies (Partner Companies) to participate**

**5.3.1** The top 500 companies have been identified by the Ministry on the basis of their average CSR expenditure of the last three years. Apart from these, any other company/ bank/ financial institution desirous of participating in the Scheme, may do so with the approval of the Ministry of Corporate Affairs (MCA), which would take a view keeping in view under represented sectors and areas in the above mentioned 500 companies.

**5.3.2** In case the Partner Company cannot directly provide such internship opportunities in its own company, it may tie-up with:

- Companies in its forward and backward supply chain (e.g. suppliers/ customers/ vendors), or;

- Other Companies/Institutions in its Group, or otherwise.

**5.4 Support and Benefits:** This is a Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme. Details of the support, financial benefits and funding pattern under the Scheme are given below:

**5.4.1 Monthly assistance to the interns:** Monthly assistance of Rs. 5,000 will be paid to the interns for the entire duration of 12 months of the internship. Out of this, every month the company, based on the attendance and related company policies regarding good conduct, etc. will release Rs.500/- to each intern from the Company's CSR funds. Once the Company makes the payment, the Government will pay Rs.4,500 to the candidate through Direct Benefit Transfer to the intern's Aadhaar seeded bank account. In case, any Company wishes to provide monthly assistance over and above Rs.500, it may do so from its own funds.

**5.4.2 Grant for incidentals:** A one-time grant for incidentals of ₹6,000 will be disbursed to each intern by the government through Direct Benefit Transfer, upon the intern's joining at the internship location.

**5.4.3 Training cost:** Expenditures associated with the training of interns under the Scheme, would be borne by the company from its CSR funds, as per the extant rules.

**5.4.4 Administrative cost:** As covered under Companies (CSR Policy) Rules, 2014, up to 5% of the CSR expenditure incurred under this Scheme may be booked as administrative costs by the company.

**5.4.5 Insurance coverage:** Insurance coverage shall be provided to each individual intern under insurance schemes of the Government of India, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, for which premium amount shall be provided by Government. In addition, the company may also provide additional accidental insurance coverage to the interns.

## **5.5 Implementation Mechanism**

**5.5.1** The Scheme will be implemented through an online portal ([www.pminternship.mca.gov.in](http://www.pminternship.mca.gov.in)) developed by the Ministry of Corporate Affairs. The Portal will serve as a centralized platform for end-to-end Scheme implementation and internship lifecycle management.

**5.5.2 Process for posting internship opportunities:** A dedicated dashboard will be provided to each Partner Company on the Portal, for posting Internship opportunities. The Internship opportunities would contain details of the internships being offered, such as location of the internship, nature of the internship, minimum educational qualification required, any facilities provided by the company, etc.

**5.5.3 Registration/Application Process for the candidates:** Eligible candidates would have to register themselves on the Portal. Based on the information provided by the candidates, a resume will be generated by the Portal. A browsing facility will be made available to candidates

for preferred sectors, functional roles, locations, and other criteria. Candidates may then apply for up to five (5) internship opportunities based on their preferences, including location (state, district), sector, functional role, and qualifications.

**5.5.4 Shortlisting and Selection:** A pool of candidates would be shortlisted for each internship opportunity through the Portal. The shortlisting process will be based on the candidates' preferences and the requirements posted by the companies. In the shortlisting process, criteria that prioritize lower employability and ensure broader representation across the applicant base will be considered. The shortlisting criteria is aimed at promoting diversity and social inclusivity in the internship program. To ensure the above, the Portal will use tools to give representation to all such segments of the population, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes as well as Persons with Disabilities. Depending on the number of offers for each internship, approximately twice /thrice as many names, along with the Resume of the candidates, will be sent to the company for selection. Companies would be able to select candidates and make internship offers based on their respective selection criteria and processes. Once an offer is sent by the company to the candidate, the candidate will be able to convey acceptance through the Portal. A Detailed Implementation Mechanism for the Pilot Project is given in Annexure-I. This mechanism would be as prescribed by this Ministry.

**5.5.5** It is clarified that an offer of internship would not give rise to any contractual or legal relationship of employer-employee between the Ministry, or the concerned company, and the selected intern. It is further clarified that such an offer of internship can neither be construed to be in the nature of an offer or promise of future employment by the concerned company or Ministry, during or after the period of internship.

**5.5.6 Operational Guidelines:** Detailed operational guidelines for the companies and the youth to participate in the Pilot Project through the Portal, will be provided on the Portal.

**5.6 Recognition of Best Practices:** The Ministry will establish a transparent process to recognize and award interns, companies based on their exceptional performance, innovation, and other criteria.

**5.7 Grievance Redressal Mechanism:** A grievance redressal mechanism to address the concerns and issues faced by stakeholders will be established to ensure timely resolution and enhance overall satisfaction of the users. The key features of the grievance redressal system are listed below:

- i) **Internship Portal:** All stakeholders including interns, companies, etc. will be able to submit their queries or grievances via the query redressal tools including chatbots linked to the Portal. These tools are envisaged to facilitate easy registration of the queries, real time tracking, and updates on the resolution status.
- ii) **Dedicated call Centre:** A multilingual call center will be established to address grievances/ queries received through the helpline.



**6. Administrative and Monitoring framework**

**6.1** There shall be a Monitoring and Steering Committee (MSC) to oversee design, implementation, operations, and other aspects of the Scheme. The MSC will comprise of officers from MCA, other Ministries/ Departments and representatives from the industry. The MSC will be empowered to make recommendations including but not limited to any modifications in the guidelines, eligibility, selection criteria, communication and outreach strategy, monitoring, evaluation, etc of the Pilot Project. The Ministry may also constitute any other committee(s) for effective Scheme implementation, review, and coordination.


**6.2** A concurrent monitoring, evaluation and learning (MEL) framework shall be developed so that timely corrective actions may be taken. A dashboard indicating key performance indicators (KPIs), periodic data reports and performance scorecards shall be used to regularly monitor and evaluate the end-to-end implementation across all fronts. Independent evaluation as well as periodic assessment/ evaluation studies will be undertaken.

**7. Communication, Awareness and Capacity Building:** Communication, advocacy, and capacity-building initiatives will be undertaken to effectively promote the Scheme to raise awareness and highlight its benefits. FAQs, user manuals, instructional videos, and informational materials will be provided on the Portal to facilitate participation of candidates and industry.

**8. Coordination with the State Governments:** Coordination with the State Governments/ PRIs/ ULBs would be done as per requirements.

**9. Learnings from the Pilot Project:** Keeping in mind the volume and complex nature of the Scheme, Pilot Project is a pivotal phase that allows for testing concepts, strategies and systems before a full-scale implementation. Based on the feedback received and evaluation of outcomes during the implementation of the Pilot Project, lessons drawn shall be collated by the Ministry. The same will be factored in while rolling out the first phase of the PM Internship Scheme, as announced in the Budget 2024-25.

**10.** This issues with the approval of Hon'ble Minister of Corporate Affairs.

  
**(Anuradha Thakur)**  
**Additional Secretary**

To,

1. Director General of Corporate Affairs, Ministry of Corporate Affairs
2. All Regional Directors and
3. All Registrar of Companies.

Copy to:

1. Finance Secretary and Secretary, Department of Public Enterprises
2. Secretary, Coordination, Cabinet Secretariat
3. Secretary, Department of Economic Affairs
4. Secretary, Department of Expenditure
5. Secretary, Department of Financial Services
6. Secretary, Ministry of Labour & Employment
7. Secretary, Department of Higher Education
8. Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
9. Secretary, Ministry of Youth Affairs and Sports
10. Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology
11. All the Chief Secretaries of the State Governments/ UTs with the request to nominate a nodal officer for the Scheme.
12. Shri Saurabh Shukla, Director, Prime Minister Office
13. PS to Hon'ble Minister of Corporate Affairs
14. PS to Hon'ble Minister of State of Corporate Affairs
15. PPS to Cabinet Secretary
16. Chief Controller of Accounts, M/o Corporate Affairs
17. Guard File

**Implementation Mechanism**

Ministry of Corporate Affairs shall develop the Portal available at [www.pminternship.mca.gov.in](http://www.pminternship.mca.gov.in). The Portal will serve as a centralized platform for end-to-end Scheme implementation and internship lifecycle management.

2. A broad overview of the Portal and other implementation processes is given below:

**2.1 List of Partner Companies:** The list of Partner Companies shall be displayed on the Portal.

**2.2 Internship opportunities:** Internship opportunities may be posted by the Partner Companies on the Portal. The Internship opportunities would contain details of the internships being offered, such as location of the internship, roles/ functions of the internship, minimum educational qualification required, other special requirement, any facilities provided by the company etc.

**2.3 Candidate Registration and Profile Creation:** Candidates must first be registered on the Portal through Aadhaar authentication or eKYC. Information such as name, address, educational qualifications, certifications (if any), and other relevant details to be provided by the candidates as specified on the Portal. Proof of educational qualifications and certifications would have to be uploaded by the candidates. Additionally, candidates must submit a self-declaration on the Portal, affirming that all eligibility requirements specified in these guidelines are met and that none of the ineligibility criteria apply. Based on the submitted details, a Resume will be generated by the Portal for the candidate.

**2.4 Candidate Application:** After the Aadhaar authentication by the candidates, a browsing facility will be made available to candidates for browsing through internship opportunities, based on their preferred sectors, functional roles, locations, and other criteria. Candidates may then apply for up to five (5) internship opportunities based on their preferences, including location (state, district), sector, functional role, and qualifications.

**2.5 Shortlisting of Candidates:** A pool of candidates would be shortlisted for each internship opportunity by the Portal. Depending on the number of offers for each internship, approximately twice/thrice as many applications would be shortlisted to be sent to the company. In the shortlisting process, criteria that prioritize lower employability and ensure broader representation across the applicant base will be considered. The shortlisting criteria is aimed at promoting diversity and social inclusivity in the internship program. To ensure the above, the Portal will use tools to give representation to all such segments of the population, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes as well as Persons with Disabilities

**2.6** This pool of shortlisted candidates would then be forwarded to each company for selection.

**2.7 Selection of Candidates:** From the shortlisted group, companies would be able to choose candidates based on their respective selection criteria and processes. Internship offers to the candidates to be sent by the Company through the Portal. Once an offer is sent by the company to the candidate, the candidate would be able to convey acceptance through the Portal. A candidate may receive up to two (2) internship offers in one cycle. A model format of the Offer Letter will be available on the Portal for the companies to use.

**2.8 Internship Document Generation:** Upon a candidate's acceptance of the offer, the Portal would automatically generate an Internship Document that clearly outlines the details of the internship, including the roles and responsibilities of both the intern and the company. A model format of the Internship Document will be available on the Portal.

**2.9 Internship Joining:** Once the candidate joins the internship, the company would confirm this on the Portal. This confirmation will initiate the release of ₹6,000 as a grant for incidentals, which will be disbursed to the candidate by the government through Direct Benefit Transfer.

**2.10 Internship:** Each month, the company will pay ₹500 and report this payment on the Portal. Following this confirmation, ₹4,500 will be released by the government, which would be disbursed to the candidate through Direct Benefit Transfer (DBT).

**2.11 Completion & Certification:** Upon successfully completing the internship, a Certificate of Completion would be issued by the Partner Company to the candidate. A model format of the Certificate will be available on the Portal. The Certificate shall be issued only by the participating Partner Companies.

### **3. Guidelines for the Companies**

**3.1** The company is expected to provide the person an actual working experience on a skill in which the company is directly involved. It shall be strictly ensured that at least half of the internship period would be in the actual work/ real-life business environment, not in classroom.

**3.2** In case the company cannot directly provide internship opportunities, it may tie-up with:

- Companies in its forward and backward supply chain (e.g. suppliers/ customers/ vendors) or
- Other companies/institutions in its group; or otherwise.

**3.3** Companies are advised not to prescribe qualification higher than necessary for the internship.

**3.4** Companies must not offer internships for unskilled roles such as cleaning, delivery, porter, security guard, office boy etc.

3.5 Companies are advised to ensure that the internship offered under PM Internship Scheme is separate from other skill / apprenticeship/ internship/ student training programme offered by them under any other Central Government or State Government scheme.

3.6 Supervisors or mentors must be assigned by the companies to each intern upon joining. Additionally, companies are encouraged to provide or enhance the soft and employability skills of each intern.

3.7 The participating Partner Companies are expected to steer the internship management programme and the different internship opportunities offered across their company and others in their forward and backwards supply chain (e.g. suppliers/ customers/ vendors) or other companies/ institutions in its group.

3.8 Companies shall follow their own mechanism for assessing the candidates on a periodic basis. Quarterly Assessment Report of the candidates would have to be uploaded by the company on the Portal.

3.9 In case an intern **withdraws** or **drops out** of the internship before completion, the company must communicate this information to the government via the Portal by marking the intern as a 'Dropout'. This will ensure that no further payments are disbursed to the candidate, by the government. The company's standard policies regarding attendance, code of conduct, and dropout shall be applied. **Generally, an intern will be considered a dropout if they stop attending to their internship requirements suddenly and without notice to their Mentor/ supervisor and fail to respond and/or rejoin despite two attempts at communication over a reasonable period by the mentor or supervisor, or if they express an unwillingness to continue.** Such candidates will not be permitted to rejoin, and no Internship Certificate will be issued to them. Furthermore, they will be disqualified from applying for any internship for one year under this Scheme.

3.10 It is clarified that an offer of internship would not give rise to any contractual or legal relationship of employer-employee between the Ministry, or the concerned company, and the selected intern. It is further clarified that such an offer of internship can neither be construed to be in the nature of an offer or promise of future employment by the concerned company or Ministry, during or after the period of internship.

#### 4. Guidelines for the Candidates

4.1 The rules and regulations of the establishment, including those related to timings, holidays, leaves, conduct, and discipline, shall be adhered to by the intern.

4.2 In case of a medical emergency, the demise of a family member, or such extenuating and emergency circumstances, a sabbatical of up to two months may be granted to the intern, in accordance with company policies and/or any directives issued by the Ministry from time to time. No financial assistance shall be provided during the sabbatical period; however, the intern shall be permitted to rejoin and complete the remaining duration of the overall 12-month

internship period. If the sabbatical period exceeds two months, the candidate will be required to discontinue and may reapply in the next internship offer cycle.

5. **Recognition of performance:** Interns will undergo continuous evaluation of their performance and conduct by the companies in accordance with the companies' policies. To build confidence and create aspirational value for the Scheme, companies are encouraged to recognize the outstanding interns, and this recognition may be displayed on the companies' websites and on this Portal.

